[11] SEAT No._____ No. of Printed Pages: 4

# SARDAR PATEL UNIVERSITY, V.V.NAGAR

## B.A. (MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM)

## SEMESTER – 3

Time: 10:00 A.M To 12:00 P.M
Date: 12-01-2021, Tuesday

**UA03ITRA21** પત્રકારત્વમાં હિન્દી અને અંગ્રેજી અનુવાદની જરૂરિયાત 1

Marks: 70

---

પ્રશ્ન 1 નીચેના પ્રશ્નોમાંથી કોઈ બે પ્રશ્નોના જવાબ લખો. [40]

૧. વિવિધ માધ્યમોમાં અનુવાદની આવશ્યકતા વિસ્તારથી જણાવો.

૨. અનુવાદ કરવામાં કેવા પ્રકારની ભૂલો ન રહેવી જોઈએ? વિગતવાર સમજાવો.

૩. અખબાર જેવા જાહેર માધ્યમમાં યોગ્ય અનુવાદ ન થાય તો શું પરિણામ આવી શકે? જણાવો.

૪. પુસ્તક અને અખબારના સમાચારના અનુવાદમાં શો તફાવત છે?

પ્રશ્ન 2 નીચેનામાંથી કોઈ બે ફકરાનો અનુવાદ કરો.. [30]

૧.

**क्या आने वाले समय में मोबाइल फोन के साथ चार्जर और ईयरफोन मिलना बंद हो जाएंगे?**

बीते कई सालों से जब भी एपल अपना कोई नया आईफोन लॉन्च कर रहा होता है तो भारतीय सोशल मीडिया पर एक चुटकुला चर्चा में आ जाता है. बेहद घिस चुके इस चुटकुले में कहा जाता है कि इस महंगे आईफोन को खरीदने के लिए तो किडनी बेचनी पड़ेगी. अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में जब आईफोन-12 सीरीज लॉन्च हुई तो हर बार की तरह यह चुटकुला फिर-फिर दोहराया गया. बस, इस बार नया यह था कि एक की बजाय दोनों किडनियां बेचे जाने की बात कही जा रही थी. कहा गया कि पहली किडनी तो केवल फोन खरीदकर घर लाने में खर्च हो जाएगी. इसका इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए चार्जर, हेडफोन और बाकी एक्सेसरीज की ज़रूरत भी होगी और इन्हें खरीदने के लिए दूसरी किडनी का सौदा भी करना पड़ सकता है.

एपल ने इस महीने आईफोन-12 सीरीज के चार मोबाइल फोन - आईफोन-12, आईफोन-12 मिनी, आईफोन-12 प्रो और आईफोन-12 प्रो मैक्स - लॉन्च किए हैं. 30 अक्टूबर से भारतीय बाज़ार में उपलब्ध हो रहे इन मोबाइल फोन्स की कीमत 70,000 से 1,30,000 रुपए के बीच होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है. ऐसी भारी-भरकम कीमत वाला आईफोन-12 अपनी लॉन्चिंग के बाद से अपनी 5-जी तकनीक या किसी भी और फीचर से ज्यादा इस बात के लिए चर्चा बटोर रहा है कि इसके साथ वॉल-चार्जर (चार्जिंग एडॉप्टर) और ईयरफोन्स नहीं दिए जा रहे हैं. यानी, आईफोन-12 के बॉक्स में मोबाइल फोन के अलावा केवल यूएसबी-सी टाइप केबल ही होगी.
एक्सेसरीज न देने के इस फैसले पर एपल का कहना है कि कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-वेस्ट) और अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ऐसा किया है. एपल के मुताबिक यह फैसला न

सिर्फ मोबाइल फोन पर लगने वाले कच्चे माल की लागत कम करेगा बल्कि इससे रिटेल बॉक्स का साइज भी छोटा होगा जिससे ढुलाई यानी ट्रांसपोर्टेशन की लागत भी कम होगी.

२.

## बिहार के लोगों को इलाज के लिए कब तक दिल्ली और नेपाल जाना पड़ेगा

सहरसा के सदर अस्पताल के जनरल वार्ड में किसी मुर्दाघर जैसा सन्नाटा था. वार्ड इतनी गंदगी और पेशाब की बदबू से भरा था कि मरीज़ों को सुपरइंफेक्शन (अस्पताल में बुरी परिस्थितियों की वजह से होने वाला संक्रमण) होने की पूरी-पूरी गुंजाइश थी. मरीज़ और उनके परिवार वाले इसी गंदगी में वक़्त काट रहे थे. हम अस्पताल का जायज़ा ले ही रहे थे कि एक लड़के ने आकर बताया कि अस्पताल के डॉक्टर रंजीत मिश्रा ने अपने निजी क्लिनिक पर पिता का इलाज कर तो दिया लेकिन ऑपरेशन के बाद सूजन आ गई है. निजी क्लिनिक में पैसा ज़्यादा लग रहा था तो डॉक्टर ने वापस सरकारी अस्पताल में जाने की सलाह दी और कहा कि वे वहीं उन्हें देखते रहेंगे.

एक और बुज़ुर्ग मरीज़ ने अपने पैर के अंगूठे पर बंधी मोटी पट्टी दिखाते हुए कहा कि वह पांच दिन से यहां हैं और डॉक्टर ने उन्हें बताया है कि अंगूठा काटना पड़ेगा लेकिन एक्स-रे होने के बाद भी अब तक ऑपरेशन नहीं हो सका है. साल 1954 में सहरसा को ज़िला घोषित किया गया और तबसे ही ये सदर/ज़िला अस्पताल मौजूद है. लेकिन इतने पुराने अस्पताल में आज तक आईसीयू सेवा शुरू नहीं हो सकी है.

अस्पताल के मुख्य दरवाज़े के पास कई लोग हमें घेर कर अपनी समस्याएं सुनाने लगते हैं जिनमें अस्पताल के स्टाफ के लोग भी थे. अस्पताल की ज़मीन पक्की नहीं थी. किसी ने कहा कि यहां बरसात के मौसम में इतना पानी भर जाता है कि शायद ही कोई मरीज़ उन दिनों यहां आने का सोचे. लोग बताते हैं कि अगर प्राइवेट में किसी को आईसीयू में भर्ती करवाना हो तो 3 हज़ार रूपए दिन का लगता है. अस्पताल के ही स्टाफ ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि यहां डॉक्टर काम ही नहीं करना चाहते हैं और ना पर्याप्त डॉक्टर हैं. ये हालात सिर्फ़ यहीं के नहीं हैं, ऐसी बुनियादी सुविधाएँ बिहार के बहुत से हिस्सों में नहीं दिखीं. लोग बताते हैं कि निजी क्लिनिक पर ले जाने के लिए दलाल भी यहां घूमते मिल जाएंगे.

३.

## तेजस्वी का सरकारी नौकरियों का वादा बदल सकता है देश की सियासत

तेजस्वी यादव ने चुनाव अभियान की शुरुआत में ही जिस तरह से बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, उससे नीतीश ही क्या, खुद भाजपा तक चकरा गई. केंद्र सरकार जिस तरह से निजीकरण करने और सरकारी नौकरियां खत्म करने, जबरन रिटायर करने की नीति पर चल रही थी, और पूरे देश में कोई तेज विरोध का स्वर न दिखाई देने के बीच, तेजस्वी ने बेरोजगारी को न केवल मुद्दा बनाया बल्कि साफ-साफ कह भी दिया कि वे दस लाख तो केवल सरकारी नौकरियां ही देंगे, और बाकी रोजगार जो होंगे, वो अलग.

रोजगार के मामले में इतनी स्पष्टता से दावा देश की राजनीति में अभी तक किसी ने नहीं किया था. साल में करोड़-दो करोड़ रोजगार देने के वादे तो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से ही किए जाते रहे लेकिन उनमें इतनी स्पष्टता कभी नहीं रहती थी कि ये रोजगार सरकारी होंगे या निजी क्षेत्र के या स्वरोजगारों की बात की जा रही है.

चुनाव अभियान की शुरुआत में जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, तब उन्हें उम्मीद नहीं रही होगी कि ये अकेला मुद्दा ही गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन बाद में जिस तरह से उन्हें इस मसले पर सभी समुदायों का समर्थन मिला, उससे निश्चित ही वे बेहद उत्साहित हुए हैं. यही कारण रहा कि तेजस्वी ने फिर हर जनसभा और साक्षात्कार में 10 लाख सरकारी नौकरियों के वादे को बार-बार दोहराकर जन-जन तक पहुंचा दिया. इस जन समर्थन को देखते ही तेजस्वी ने अपने वादे में बेरोजगारों को नौकरी नहीं तो बेरोजगारी भत्ते को भी शामिल कर लिया, और नौकरियों के लिए परीक्षा शुल्क में छूट का वादा भी कर लिया.

जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया तो भाजपा और जेडीयू ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि चुनावी वादों को जनता बहुत गंभीरता से नहीं लेती रही है. स्थिति यहां तक रही कि नीतीश कुमार और भाजपा नेताओं ने तेजस्वी के वादे का मजाक तक उड़ाना शुरू कर दिया कि इतनी नौकरियों के लिए धन कहां से आएगा.

४.

**एनएच (नेशनल हाइ वे)-44 को कश्मीर के लोगों और सैनिकों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत कैसे बन गया?**

श्रीनगर शहर के बाहर, नेशनल हाइवे नंबर 44 पर तैनात सीआरपीएफ़ के जवानों पर हमला किया गया. मिलिटेंट्स के इस हमले में दो जवान मारे गए और तीन अन्य, जिनमें एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी शामिल था, घायल हो गए. यह कश्मीर के इस हाइवे पर होने वाला पहला हमला नहीं था. अगर इतिहास पर नज़र दौड़ाएं और अभी के हालात भी देखें, तो शायद यह हमला आखिरी भी नहीं होगा. सालों से यहां हो रहे हमलों ने कश्मीर के इस हाइवे को सुरक्षा एजेंसियों के लिए तो सरदर्द बनाया ही है, यह कश्मीर के लोगों के लिए भी एक बुरा सपना बन गया है.

सवाल यह पैदा होता है कि ये हमले हो क्यों रहे हैं, इन्हें कौन अंजाम दे रहा है और क्यों अब एनएच-44 लोगों और सुरक्षा एजेंसियों के लिए सरदर्द बन गया है. इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा होगी लेकिन पहले ज़रूरी है कि कश्मीर में इस हाइवे का महत्व समझा जाये. कश्मीरको देश के अन्य राज्यों से जोड़ता है नेशनल हाइवे-44. वैसे तो यह हाइवे, जम्मू और श्रीनगर के बीच में 294 किलोमीटर का है, लेकिन यहां विशेष तौर पर बात हो रही है जवाहर टनल से श्रीनगर तक के इसके लगभग 95 किलोमीटर हिस्से की. यह कश्मीर घाटी का इकलौता राज मार्ग है और इसका ज़्यादातर हिस्सा मिलिटेन्मी प्रभावित दक्षिण कश्मीर से होकर जाता है. यह हाइवे पहले



[P.T.O.]

एनएच-1ए हुआ करता था जो कश्मीर घाटी के विभिन्न शहरों, कस्बों और गांवों से होकर जाता था. ज़ाहिर है कि हर दिन सैन्य बलों के काफिलों को भी कश्मीर में आने-जाने के लिए इसी का इस्तेमाल करना होता था.

90 का दशक खत्म होते-होते, कश्मीर में भी देश के अन्य भागों की तरह ट्रैफिक बढ़ने लगा था और एक नए, बड़े हाइवे की ज़रूरत महसूस हुई. 2010 के आस-पास इस नए हाइवे पर काम शुरू हुआ और सारी चीजों को सामने रखते हुए सारे आबादी वाले बाइपास कर दिये गए. जो नया हाइवे, एनएच-44 के नाम से, बना यह ज़्यादातर धान के खेतों के बीच से होकर गुज़रता है, जहां दूर-दूर तक न तो बाज़ार हैं न आबादी. यह एनएच-44, 2018 के मध्य में ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था.